ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-4* July- 2021
Anthology : The Research

पर्यावरण एवं सामुदायिक जन जागरूकता (नैनीताल के संदर्भ में)

Environment and Community Public Awareness (with reference to Nainital)

Paper Submission: 03/07/2021, Date of Acceptance: 14/07/2021, Date of Publication: 25/07/2021

मनीषा भूषण
असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय महिला महाविद्यालय,
बदायूँ, उत्तर प्रदेश, भारत

सुजाता मैनवाल
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग,
मेरठ कॉलेज,
मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र में शोध शीर्षक ‘‘पर्यावरण एवं सामुदायिक जन जागरूकता (नैनीताल के संदर्भ में)‘‘ नैनीताल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित नैनी झील व आसपास के अन्य जिलों पर बढ़ रहे प्रदूषण के दुष्परिणामों एवं इन झीलो का पर्यावरण पर प्रभाव तथा इनकी संरचना में बदलाव से उभरने वाले दुष्परिणामों का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य हेतु वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध विधि प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों को भी अपनाया गया है तथा नैनीताल जिले के लगभग 100 लोगों से आंकड़ों को एकत्रित करते हुए स्वनिर्मित साक्षात्कार परिसूची का प्रयोग किया गया है। शोध का निष्कर्ष कई ऐसे सुझाव प्रस्तुत करता है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अति आवश्यक है।

In the presented research paper, the research title is "Environment and Community Public Awareness (with reference to Nainital)" Nainital, the consequences of increasing pollution on Naini Lake and other surrounding districts located in Nainital district of Uttarakhand state and the environment of these lakes. The effect on and the side effects emerging from changes in their structure have been studied. Descriptive survey research method, primary and secondary sources have also been adopted for the present research work and self-made interview schedule has been used by collecting data from about 100 people of Nainital district. The conclusion of the research presents many such suggestions which are very important for environmental protection.

मुख्य शब्दः नैनीताल,पर्यावरण,सामुदायिक जन जागरूकता, जन आंदोलन, झीलें, सहभागिता, प्रदूषण
अधिनियम।

प्रस्तावना

नैनीताल भारत के उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक नगर और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यह जिले का मुख्यालय भी है। कुमायूँ क्षेत्र में नैनीताल का विशेष महत्व है। यह ‘छखाता’ परगने में आता है। ‘छखाता’ नाम ‘षष्टिखात’ से बना है। ‘षष्टिखात’ का तात्पर्य साठ तालों से है। इस अंचल में पहले साठ मनोरम ताल थे। इसलिए इस क्षेत्र को ‘षष्टिखात’ कहा जाता था। आज इस अंचल को ‘छखाता’ नाम से अधिक जाना जाता है। इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी जगह झीलों से घिरी हुई है। पहाड़ों के बीच बसा यह स्थान झीलों से घिरा हुआ है। इनमें से सबसे प्रमुख झील नैनी झील है जिसके नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा है। एक महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ के अनुसार नैनीताल ‘64 शक्तिपीठों’ में से एक है। इन शक्तिपीठों का निर्माण सती के विभिन्न अंगों के गिरने से हुआ है। जब भगवान शिव सती को जली हुई अवस्था में ले जा रहे थे। मान्यता है कि इस स्थान पर सती की बांयी आंख (नैन) गिरी थी जिसने नैनीताल के संरक्षक देवता का रूप लिया। इसीलिए इसका नाम नैन-ताल पड़ा जिसे बाद में नैनीताल के नाम से जाना जाने लगा। इस तालाब के उत्तरी छोर पर नैना देवी का मंदिर है, जहां पर देवी शक्ति की पूजा होती है।

विषय विस्तार

किसी भी जगह के पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहां के रहने वाले मूल निवासियों पर निर्भर करती है ऐसा ना केवल प्रास्थतिवश अपितु भावनात्मक लगाव ही इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैनीताल जिला झीलों का शहर है व यह झीले ना केवल यहां के पर्यावरण पर व्यापक असर डालती है, बल्कि आसपास के पर्यावरण पर भी इनका अच्छा खासा असर है। परंतु पिछले कुछ वर्षों का घटनाक्रम इस बारे में सोचने को मजबूर करता है कि इनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिसमें एक आम आदमी की भूमिका व उसके दैनिक प्रत्यय निर्णायक हो। ऐसा इसलिए जरूरी था क्योंकि नैनी झील का पानी वर्ष 2000 से पहले केवल दो बार 1923 व 1980 में ही जीरो लेवल तक पहुंचा था। किंतु वर्ष 2000 के बाद ऐसा 15 बार हो चुका है। वर्ष 2017 में झील का पानी शून्य के निशान से 18 फीट नीचे पर चला गया था। न केवल नैनीताल बल्कि आसपास की झीलों के तंत्र में शामिल सूखा ताल का उल्लेख इसलिए जरूरी है क्योंकि नैनी झील के मुख्य स्रोत के रूप में सुखा ताल एक निर्णय भूमिका निभाती है।

नैनी झील से सटे बाजारों एवं होटल तंत्र का नैनी झील पर कितना असर है। पर्यटकों की संख्या इस पर कितना असर डाल रही है व अन्य बाहरी कारकों की भूमिका।

पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में पर्यटकों की संख्या मैं हर वर्ष इजाफा होता जा रहा है। कुमायूं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चारू सी पंत के अनुसार नैनी झील का 32 प्रतिशत पानी शहर की जरूरत में ही इस्तेमाल हो जाता है और जब यहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता है तो झील के पानी पर निर्भरता और अधिक बढ़ जाती है। पर्यटकों की संख्या नैनीताल शहर की संख्या के बराबर पहुंच जाती है। वर्ष 2013 में पर्यटकों की संख्या 7 लाख के करीब थी। तो वर्ष 2014 में यही संख्या साढे सात लाख पार कर गई। वर्ष 2016 में नैनीताल आने वाले पर्यटकों की संख्या सवा आठ लाख के पार रही जबकि 2018 में यह आंकड़ा साढे नौ लाख पार कर गया। टूरिस्ट सीजन में वीकेंड में तकरीबन 4000 से 5000 गाड़ियां नैनीताल पहुंचती है। नैनीताल व आस पास के इलाकों में होटल कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे हैं। जो कि इसके परिस्थितितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। होटलों में पानी की फिजूलखर्ची झील के पानी पर निर्भरता को और अधिक बढ़ा रही है। सूखा ताल का संरक्षण व उस पर हो रही निर्माण गतिविधियों का असर नैनी झील पर सबसे अधिक पड़ रहा है क्योंकि नैनी झील के पानी के स्रोतों में सूखा ताल अहम भूमिका में है।

उत्तराखण्ड राज्य में समय≤ पर अनेक प्रमुख जन-आन्दोलन हुए हैं। जिनमें से कुछ का मकसद अपना अधिकार पाना था तो कुछ का मकसद उत्तराखण्ड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाना था। कई आन्दोलन वन सम्पदा को बचाने के लिए किये गए जो कि आज भी हमारे लिए मिसाल हैं। जिनमें चिपको आन्दोलन प्रमुख है। जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, तो उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में 80 के दशक में चले एक अनूठे आन्दोलन 'चिपको आन्दोलन' का जिक्र होना स्वाभाविक है। वन संरक्षण के इस अनूठे आन्दोलन ने न सिर्फ देश भर में पर्यावरण के प्रति एक नई जागरूकता पैदा की बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'इको फेमिनिज़्म' ;म्ब्व् थ्मउपदपेउद्ध या 'नारीवादी पर्यावरणवाद' का एक नया मुहावरा भी विकसित किया। उत्तराखण्ड राज्य का चिपको आन्दोलन एक घटना मात्र नहीं है। यह पर्यावरण व प्रकृति की रक्षा के लिए सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

चिपको आन्दोलन का अर्थ है कि पेडों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर जान दे देना, लेकिन पेड़ों को काटने नहीं देना। भारत में पहली बार 1927 में 'वन अधिनियम' को लागू किया गया था। इस अधिनियम के कई प्रावधान आदिवासी और जंगलों में रहने वाले लोगों के हितों के खिलाफ थे। ऐसी ही नीतियों के खिलाफ 1930 में टिहरी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। अधिनियमों के कई प्रावधानो ंके खिलाफ जो विरोध 1930 में शुरू हुआ था, वह 1970 में एक बडे आन्दोलन के रूप में सबके सामने आया। जिसका नाम 'चिपको आन्दोलन' रखा गया।

चिपको आन्दोलन की शुरूआत 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के करीब 680 हेक्टेयर जंगल ऋषिकेश के एक ठेकेदार को नीलाम कर दिया गया। इसके अंतर्गत जनवरी 1974 में रैंणी गांव के 2459 पेड़ों को चिन्हित किया गया। जिसके विरोध में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें गौरा देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया।

70 के दशक में बांज के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण हिमपुत्रियों (वहां की महिलाओं) ने यह नारा दिया कि 'हिम पुत्रियों की ललकार वन नीति बदले सरकार' वन जागे वनवासी जागे'। रैणी गाँव के जंगलों में गंूजे ये नारे आज भी सुनाई दे रहे हैं। चिपको आन्दोलन कि शुरूआत 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर में 23 वर्षीय विधवा गौरी देवी द्वारा की गई, चिपको आन्दोलनकारी महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा ("क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने के आधार") दिया गया था, जो काफी प्रसिद्ध हुआ।

चिपको आन्दोलन को अपने शिखर पर पहुँचाने में पर्यावरणविद सुन्दरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुगुणा जी ने "हिमालय बचाओ देश बचाओ" का नारा दिया। इस आन्दोलन के लिए चमोली के

चंडीप्रसाद भट्ट को 1981 में रेमन मेगसेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस समय अलकनंदा घाटी से उभरा चिपको का संदेश जल्दी ही दूसरे इलाकों में भी फैल गया। नैनीताल और अल्मोड़ा में आन्दोलनकारियों ने जगह-जगह हो रहे जंगल की नीलामी को रोका। टिहरी से ये आंदोलन सुन्दरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए 1981 से 1983 तक लगभग 5000 कि.मी. लम्बी ट्रांस-हिमालय पदयात्रा की और 1981 में हिमालयी क्षेत्रों में एक हजार मीटर से ऊपर के जंगल में कटाई पर पूरी तरह पाबंदी की मांग लेकर आमरण अनशन पर बैठे। इसी तरह से कुमायूँ एवं गढ़वाल वेळ विभिन्न इलाकों में अलग-अलग समय पर चिपको की तर्ज पर आन्दोलन होते रहे।

इन सभी आन्दोलनों की सफलता स्थानीय लोगों की जागरूकता के कारण सम्भव हो पायी।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य नैनीताल नगर के वासियों द्वारा ऐसी दैनिक गतिविधियों से संबंधित है जो झील के संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकती है। साथ ही सरकारी तंत्र के लिए भी ऐसे सुझाव हैं जिन्हें जन सहभागिता के साथ लागू करके कई महत्वपूर्ण बदलाव लाये जा सकते हैं। अध्ययन जन सहभागिता को बदलाव के लिए प्रयोग किए जाने की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। जैसे कि दूसरे राज्यों में पॉलीथिन पर प्रतिबंध होने के बावजूद सामुदायिक जनसहभागिता के अभाव में यह सफल नहीं हो पा रहा है। इनको नैनीताल के संदर्भ में मैंने इसे बिल्कुल उलट पाया। स्थानीय निवासियों दुकानदारों व होटल व्यवसाय में भी पॉलिथीन का प्रयोग काफी हद तक सीमित पाया गया। यह वहां के नागरिकों की जन सहभागिता के कारण ही हो पाया है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अभिकल्प में शोध प्रविधि के रूप में प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीयक स्रोत से प्राप्त सामग्री का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने हेतु नैनीताल जिले के लगभग 100 व्यक्तियों से स्व निर्मित साक्षात्कार परिसूची के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित किया गया। द्वितीयक स्रोतों में समाचार पत्र व पत्रिकाओं में प्रकाशित सूचनाएं, इंटरनेट वेबसाइट इत्यादि को अपने अध्ययन का आधार बनाया। जिनका उल्लेख संदर्भ सूची में भी किया गया है।

अध्ययन की विषय वस्तु एवं विश्लेषण

अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना व उनकी सहभागिता प्राप्त करना मात्र है। इसके सुधार के उपाय भी लोगों से ही आने हैं और उनका लाभ भी लोगों को ही मिलना है। इसके लिए बच्चों को पर्यावरण एवं उससे जुड़ी समस्याओं से परिचित कराना स्कूल के बच्चों को पर्यावरण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, समाज को व्यापक पैमाने पर जागरूक बनाने की दिशा में बच्चों को भागीदार बनाना, सरकारी संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, महिला एवं युवा संगठनों सैन्य इकाईयों को भी इस मुहिम में जोड़ना होगा ना सिर्फ जोड़ना बल्कि उन्हें यह भी समझाना होगा कि इस शहर का अस्तित्व पर्यावरण एवं इन झीलों पर ही आश्रित है। इनके संबंध में मेरे द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों एवं विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से साक्षात्कार के माध्यम से लगभग 20 प्रश्न पूछे गए। जिनके आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश रही। कुछ प्रश्न तथ्यात्मक थे जिनमें उनकी आयु, लिंग, नाम, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय आदि शामिल थे। इसके अलावा जो मुख्य प्रश्न थे वह इस प्रकार है - आपके अनुसार नैनीताल शहर की मुख्य समस्या क्या है? बढ़ती पर्यटकों की संख्या नैनीताल के पर्यावरण को किस तरह प्रभावित कर रही है? क्या आप नैनीताल में बढ़ते निर्माण कार्यों के विरुद्ध है? क्या आप पर्यावरण एवं झील के संरक्षण हेतु प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं? जैसे प्रश्नों के माध्यम से नैनीताल वासियों की पर्यावरण एवं वहां हो रहे निर्माण कार्यों के प्रति उनकी जागरूकता एवं उन कार्यों से पर्यावरण पर हो रहे प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में अनेक तथ्य निकल कर सामने आए व उन्हीं में कहीं न कहीं समाधान भी छुपे हुए थे।

नगर वासियों से विभिन्न प्रश्नों एवं वार्तालाप से एक तथ्य तो स्पष्ट था कि वहां का जनमानस पर्यावरण को एवं वहाँ की झीलों की प्राकृतिक सुंदरता को बचाए वह बनाए रखने के प्रति काफी हद तक जागरूक था। उनकी जागरूकता का एक छोटा सा उदाहरण वहां के टैक्सी ड्राइवर ने पेश किया जब मैंने उससे सूखा ताल पर हो रहे निर्माण कार्य से ताल पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने पर पूछा तो उसकी तरफ से इस कार्य पर तीखी प्रतिक्रिया आई की ताल के आसपास निर्माण कार्य को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए क्योंकि यदि यह झीले नहीं बचेगी व पर्यावरण दूषित होगा तो यहां कोई क्यों आएगा। इसी तरह वहां के बाजार में पॉलीथिन का प्रयोग ही ना के बराबर था। यह प्रतिबंध केवल प्रशासन की वजह से नहीं था अपितु लोगों का पर्यावरण व झीलों के प्रति उनका लगाव था। अतः स्पष्ट है की कानूनों के क्रियान्वयन के साथ-साथ उसके प्रति जनमानस का संवेदनशील होना बेहद जरूरी है।

समस्याएं एवं चुनौतियां

नैनीताल जिले में मुख्य समस्या पानी की आ जाती है। झील का घटता जल स्तर व पर्यटकों की बढ़ती संख्या इस समस्या को और भी अधिक गंभीर कर देती है। दूसरी बड़ी समस्या भूस्खलन की है। पर्यटन सीजन में एकदम से पर्यटकों की वाहनों

की संख्या में इजाफा होने से पार्किंग की समस्या गंभीर रूप ले लेती है जो कि पर्यावरण प्रदूषण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।नैनीताल जिस नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता एवं आबोहवा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है वही अपना महत्व खो देता है। अवांछित निर्माण कार्य भी नैनीताल व आसपास के क्षेत्रों की बड़ी समस्या है। सूखाताल क्षेत्र में निर्माण प्रक्रिया के परिणाम स्वरुप नैनी झील के जल स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जिसकी वजह से उसकी प्राकृतिक जलीय स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होने लगे हैं। नैनीताल में यह समस्याएं अनेक चुनौतियों वहां के प्रशासन तंत्र, आम नागरिक एवं होटल जैसे अन्य व्यवसायों से जुड़े लोगों के समक्ष एकदम से खड़ी हो जाती है। जैसे कि पर्यटन उद्योग जो यहां की आय का प्रमुख स्रोत है व पानी की समस्या के बीच में संतुलन स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। अधिकांश होटलों में जगह की कमी के कारण पार्किंग की समुचित व्यवस्था कराना प्रशासन व आम नागरिकों के लिए एक प्रमुख चुनौती बन जाती है। साथ ही पर्यटन सीजन में पर्यटकों की अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करना भी पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाती है। जैसे कि नैनीताल शहर में सीजन में अत्यधिक सैलानियों के आगमन से पर्यटकों के वाहनों को कई घंटों तक शहर से बाहर ही रोक के रखना एक बड़ी चुनौती होती है।

सुझाव एवं निष्कर्ष

शोधार्थी द्वारा नैनीताल के लोगों से साक्षात्कार के द्वारा ली गई राय के अन्वेषण एवं स्वयं के अध्ययन के आधार पर कुछ सुझाव जो निकल कर सामने आए इस प्रकार से हैं जैसे वर्षा जल संचयन सभी होटलों के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। यदि कोई होटल इस कार्य में विलंब करता है तो उस पर जलकर की बढ़ी हुई दरों को लागू किया जाना चाहिए। जब तक कि वह उपरोक्त को लागू ना कर ले। किसी भी नए होटल के निर्माण कार्य की तब तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह अपने यहां उपलब्ध कमरों के अनुपात में गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था न कर ले। शासन-प्रशासन द्वारा नैनीताल शहर के बाहर खाली पड़े स्थानों को पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है जो कि नगर विकास के लिए नए आय के स्रोत के रूप में भी लाभप्रद रहेगा। किसी भी नए निर्माण कार्य को इसी परिस्थिति में मंजूरी मिलनी चाहिए कि वह नैनी झील के जल स्रोतों को बाधित ना करें। साथ ही पहाड़ों में भूस्खलन एक बड़ी समस्या है। जिससे नैनीताल भी अछूता नहीं है। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नैनीताल शहर में प्रतिवर्ष बढ़ती सैलानियों की संख्या को सीमित किया जाना चाहिए। जो कि वहां की अधिकांश समस्याओं का समाधान भी होगा। इन सभी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब वहां के निवासी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें व इसके प्रति जागरूक हो। सरकार द्वारा कानून लागू किए जा सकते हैं परंतु उनको पूर्णतया सफल बनाना वहां के नागरिकों पर ही निर्भर करता है। जब बात पर्यावरण संरक्षण की हो तो कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण सामुदायिक जन जागरूकता हो जाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान Charu C- Pant] Department of Geology, Kumaun University] Nainital*
2. *Environment problems of Naini & Lake Basin with special reference to slope instability and dwinding water resources] 11th August 2017]Raj Bhawan] Dehradun*
3. *Shakeel Rahman] Islamic University of Science and Technology] Awantipura] Jammu and Kashmir] India*
4. *Sustainable Tourism Development in India with Special Reference to Nainital & Uttarakhand*
5. *Article Published by Neeraj Santoshi in Hindustan times] Nainital May 27]2019*
6. *विकिपीडिया*
7. *ni.m.wikipedia.org.wiki*
8. *(Chipko Andolan) Studyfry.com*
9. *Published on January 19, 2017*